



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एम टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल नम्बर / Appeal / File No	मूल आदेश म / O.I.O No	दिनांक / Date
	V2/ 46/RAJ/2020	05/ADC-RK/Sub-Commr/2018- 19	21-02-2019

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-080-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:	28.07.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	29.07.2020
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ महायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मूजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-

M/s Raviraj Infra Projects Pvt Ltd, 304-307 Shopping Point, Digjam Circle, Jamnagar-3691006.

इस आदेश (अपील) में व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) बर्गीकरण मूल्यांकन में सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्ट्र) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

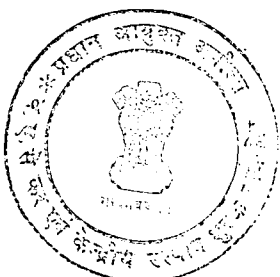
(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एवं प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपय 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपय तक अथवा 50 लाख रुपय से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी खातांक बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उक्त साथ जमा आदेश के विरुद्ध अपील की रफी हो, उमकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपय 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपय या 50 लाख रुपय तक अथवा 50 लाख रुपय से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी खातांक बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उम शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा महायुक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 of the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जत मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जत केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - सेनवेट जमा की वी गई गलत राशि
 - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विनियम (सं- 2) अधिनियम 2014 के अन्तर्भूत से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- amount determined under Section 11 D;
 - amount of erroneous Cenvat Credit taken;
 - amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामला में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरन्तुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, विन मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, समद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहाँ नुकसान किसी माल को किसी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
 - भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिविटे) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
 - यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
 - मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो छुट्टी ब्रेडॉट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (सं- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियंत्रित की गई वारिष्ठ अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
 - उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रपण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के माध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR 6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
 - पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000/- का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
 - यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होने हुए भी की लिखा पट्टी कार्य में बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of order, in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
 - यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
 - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्भालित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाना है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
 - उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Raviraj Infra Projects Pvt Ltd., Jamnagar (hereinafter referred to as "Appellant") filed appeal No. V2/46/RAJ/2020 against Order-in-Original No. 5/ADC-RKC/Sub-Commr/2018-19 dated 21.2.2019 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The brief facts of the case are that during the course of Audit of the records of the Appellant, it was observed that the Appellant had rendered services under the category of 'Commercial of Industrial Construction Service' but had not discharged service tax. Hence, Show Cause Notice No. V.ST/AR-I-JMR/6/Commr/2015-16 dated 17.4.2015 was issued to the Appellant for the period from April, 2013 to September, 2014, calling them to show cause as to why Service Tax of Rs. 1,54,52,642/- should not be demanded and recovered from them under proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (*hereinafter referred to as "Act"*) along with interest under Section 75 of the Act and proposing imposition of penalty under Sections 76, 77 and 78 of the Act.

2.1 The above Show Cause Notice was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order confirming Service Tax of Rs. 1,43,86,798/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act and imposed penalty of Rs. 1,43,86,798/- under Section 78 of the Act and Rs. 10,000/- under Section 77 of the Act.

3. Aggrieved, the Appellant has preferred this appeal on 7.7.2020 along with application for condonation of delay.

3.1 In application for condonation of delay, the Appellant has pleaded that they had received Order-in-Original No. 5/ADC/RK/Sub-Commr/2018-19 dated 21.2.2019 on 12.3.2019 and immediately forwarded to their legal consultant, however, due to lapse on the part of their consultant, they could not file appeal in time; that there is sufficient cause for delay in filing appeal and requested to condone delay in filing appeal.

4. I find that the impugned order was issued on 21.2.2019 by the adjudicating authority. As stated by the Appellant, they received the Order on 12.3.2019. The Appellant was required to file appeal within 2 months from the receipt of the said order i.e. on or before 12.5.2019, as stipulated under Section 85(3A) of the Act. However, the Appellant has filed Appeal on 7.7.2020, i.e.



after more than 1 year from due date. This appellate authority has powers to condone delay of one month in filing of appeal, over and above two months mentioned above, if sufficient cause is shown, as per proviso to Section 85(3A) *ibid*. I find that there is a delay of more than one year in filing the appeal over and above the normal period of 2 months. Thus, appeal filed beyond the time limit prescribed under Section 85 *ibid* cannot be entertained.

5. This appellate authority is a creature of the Statute and has to act as per the provisions contained in the Act. This appellate authority, therefore, cannot condone delay beyond the period permissible under the Act. When the legislature has intended the appellate authority to entertain the appeal by condoning further delay of only one month, this appellate authority cannot go beyond the power vested by the legislature. My views are supported by the following case laws :

(i) The Hon'ble Supreme Court in the case of **Singh Enterprises** reported as 2008 (221) E.L.T. 163 (S.C.) has held as under:

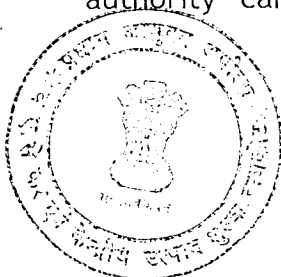
“8. ...The proviso to sub-section (1) of Section 35 makes the position crystal clear that the appellate authority has no power to allow the appeal to be presented beyond the period of 30 days. The language used makes the position clear that the legislature intended the appellate authority to entertain the appeal by condoning delay only upto 30 days after the expiry of 60 days which is the normal period for preferring appeal. Therefore, there is complete exclusion of Section 5 of the Limitation Act. The Commissioner and the High Court were therefore justified in holding that there was no power to condone the delay after the expiry of 30 days period.

(ii) In the case of **Makjai Laboratories Pvt Ltd** reported as 2011 (274) E.L.T. 48 (Bom.), the Hon'ble Bombay High Court held that the Commissioner (Appeals) cannot condone delay beyond further period of 30 days from initial period of 60 days and that provisions of Limitation Act, 1963 is not applicable in such cases as Commissioner (Appeals) is not a Court.

(iii) The Hon'ble High Court of Delhi in the case of **Delta Impex** reported as 2004 (173) E.L.T. 449 (Del) held that the Appellate authority has no jurisdiction to extend limitation even in a “suitable” case for a further period of more than thirty days.

6. I find that the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994 are *pari materia* with the provisions of Section 35 of the Central Excise Act, 1944 and hence, the above judgements would be squarely applicable to the present appeal also.

7. By respectfully following the above judgements, I hold that this appellate authority cannot condone delay beyond further period of one month as



A

prescribed under proviso to Section 85(3A) of the Act. Thus, the appeal filed by the Appellant is barred by limitation and hence, not maintainable.

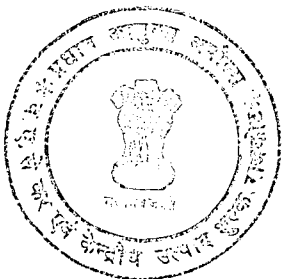
8. Apart from above, I find that pre-deposit @7.5% of service tax in dispute is required to be deposited as per Section 35F of the Central Excise Act, 1944 made applicable to service tax by virtue of Section 83 of the Finance Act, 1994 to admit the appeal. I find that the Appellant has not paid required pre-deposit but has filed stay application for waiver of pre-deposit of 7.5% of service tax on the ground that,

(i) Investigation was carried out against covering the period from 2011-12 to 2014-15 and demand for differential service tax of Rs. 2,42,72,710/- was raised and that they have discharged the said service tax liability along with interest of Rs. 1,02,94,164/-; that demand raised in SCN dated 17.4.2015 involved in the present appeal for the period from April, 2013 to September, 2014 is already covered under investigation proceedings and they have already discharged service tax for the entire period and hence, they are not required to make payment towards pre-deposit.

(ii) That considering the prima facie merits of the appeal is in their favour as evident from the facts and circumstances of the case and hence, insistence of pre-deposit of service tax would cause undue hardship and irreparable loss and requested to waive requirement of pre-deposit of tax.

9. I have gone through impugned order wherein at para 6.4, it has been observed that,

“6.4 I have carefully gone through the Show Cause Notice dated 22.4.2016 issued by the Principal Commissioner, Central Excise & Service Tax, Rajkot demanding the service tax amounting to Rs. 2,42,72,710/- along with applicable interest and penalty from the noticee pertaining the service tax not paid for the period from 2011-12 to 2014-15. The said demand has been raised for non payment of Service Tax on various services namely ‘Salaya Bhogat Pipeline income’, ‘Manpower recruitment agency’, ‘Equipment Hire income’, ‘Civil Works Income’, Tipper Hire income’, ‘Salaya Mathura Pipeline income’, ‘PCG Drainage site income’ & ‘OFC cable line laying income’. I find that the Noticee had approached the Settlement Commission for settlement of aforesaid demand notice. The Commission had finally settled the case vide its Final Order No 85/ Final Order/ ST/ KNA/ 2017 dated 08.05.2017 wherein the Service Tax liability was settled at Rs. 2,42,72,710/- along with applicable interest and imposed a penalty of Rs. 7,50,000/ on the Noticee and a penalty of Rs. 75,000/- on Shri Dharmendrasinh M. Jadeja. The Noticee has already made payment of the amount as finalized by the Settlement Commission. Since the Noticee has already paid the applicable Service Tax on the ‘Civil works Income’ to the tune of Rs. 86,23,330/-, for the period for, 2013-14 to. 2014-15 (Upto September-2014), the same needs to be deducted from the total Civil Works Income, as provided by the noticee for the present Show Cause Notice. Hence the noticee is liable to pay Service Tax to the tune of Rs. 1,43,86,798/ on the income of Rs. 11,63,98,042/- (Rs. 12,50,21,372/- - Rs.86,23,330/-). along with applicable interest, and demand to the extent of Rs. 10,65,844 / is liable to be dropped.”




A

9.1 In view of above, the adjudicating authority has already dropped service tax demand of Rs. 10,65,844/- pertaining to 'Civil Works Income' covered in SCN dated 22.4.2016 and confirmed remaining service tax demand in the impugned order. Hence, the Appellant is required to make pre-deposit @7.5% of service tax demand confirmed in the impugned order, which has not been done. The present appeal is, therefore, liable to be dismissed for non-compliance of pre-deposit under Section 35F of the Central Excise Act, 1944, also.

10. I, therefore, dismiss the appeal on limitation as well as for non compliance of requirement of pre-deposit under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 and uphold the impugned order.

11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

11. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.


(GOPI NATH)
Commissioner(Appeals)

Attested



(V.T.SHAH)

Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s Raviraj Infra Project Pvt Ltd, 304-307, Shopping Point, Digjam Circle, Jamnagar-Khambhalia Road, Jamnagar.	सेवा में, मे. रविराज इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 304-307, शॉपिंग पॉइंट, दिग्जाम सर्कल, जामनगर।
--	---

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फाइल।

